

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 4933/2025

सर्वजीत लाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जिला बलिया एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: रमेश चंद्र द्विवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए किया है:-

"i. एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 अपर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, बलिया को अपील संख्या 2008541509000016 (सर्वजीत लाल बनाम उत्तम चंद एवं अन्य), धारा 11(1) यू.पी.सी.एच. अधिनियम के तहत, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए जो उनके समक्ष लंबित है।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपील वर्ष 2009 से लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि विपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और वाद अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और अपर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, बलिया (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निर्देश देता है कि वे इसे शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से पांच महीने की अवधि के भीतर तय करें।
6. यह अपेक्षा की जाती है कि इसे संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।
7. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

16 जनवरी, 2026

विनय